बी.सी.आर. व बार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

क्या प्रावधान किए गए हैं।

मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव व जस्टिस गणेश राम मीना की खंडपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता हेमा तिवाडी की जनहित याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया था कि नारी शक्ति वंदन अभियान-2023 के तहत महिला आरक्षण अधिनियम लाया गया। जिसके तहत संसद में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया गया। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने गत 26 सितंबर को अदिति चौधरी बनाम बार कौंसिल ऑफ दिल्ली व अन्य के मामले में बार कौंसिल ऑफ दिल्ली को निर्देश दिया कि वह बार कौंसिल के चुनावों में महिला अधिवक्ताओं के लिए भी 33 फीसदी सीट आरक्षित रखें।

इस संबंध में याचिकाकर्ता ने भी बी.सी.आर. को महिला अधिवक्ताओं को 33 फीसदी आरक्षण देने के लिए 28 अगस्त को प्रतिवेदन दिया था, लेकिन उसके प्रतिवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के पद पर महिला नियुक्त हो चुकी हैं, लेकिन बी.सी.आर. में चेयरमैन व वाइस चेयरमैन के पद पर कभी भी कोई महिला नियुक्त नहीं हुई। इसलिए बी.सी.आर., हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर व जोधपुर सहित, अन्य जिला बार एसोसिएशनों में भी महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देते हुए 33 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने बार कौंसिल सहित संबंधित एसोसिएशनों से जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति संजीव...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और एक साल बाद यहां स्थायी न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत किया गया था।

परंपरा है कि मौजूदा सी.जे.आई. अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तभी करते हैं, जब उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने का आग्रह किया जाता है।

सी.जे.आई. चंद्रचूड़ के बाद वरिष्ठता सूची में जस्टिस संजीव खन्ना का नाम है। इसलिए जस्टिस खन्ना का नाम आगे बढ़ाया गया है, हालांकि, उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का होगा। 64 साल के जस्टिस खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर होंगे। सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर जस्टिस खन्ना ने 65 फैसले लिखे हैं। इस दौरान वे करीब 275 बेंचों का हिस्सा रहे हैं।

कोटा में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किराए पर रह रहा था, उसी मकान में उसकी बुआ की लड़की भी रहती थी। बुधवार रात को 8.30 बजे जब वह आशुतोष को खाने के लिए बुलाने गई, तब उसे पूरे घटनाक्रम का पता चला। इसके बाद उसने पीजी मालिक को इन्फॉर्म किया। बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंची। बताया गया कि छात्र तीसरी बार नीट यूजी की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसने बीते साल 2023 में भी कोटा में रहकर तैयारी की थी। इस साल भी वह चार-पांच महीने पहले ही कोटा आया था। जिस पीजी में छात्र आशुतोष रहता था, उसमें सुसाइड प्रिवेंशन रॉड (एंटी हैंगिंग डिवाइस) नहीं थी, जबकि जिला प्रशासन ने सभी हॉस्टल्स और पीजी संचालकों को यह डिवाइस लगाने के निर्देश दिए हुए हैं।

महाराष्ट्र व ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आनन्दीबेन पटेल, जो प्रधानमंत्री मोदी के नज़दीक मानी जाती हैं, को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद पर पाँच साल से ज्यादा समय हो गया। जो राज्यपाल अपने पद पर तीन साल से अधिक समय से आसीन हैं, उनमें शामिल हैं- गोवा के राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई, हरियाणा के राज्यपाल बंडारु दत्तात्रेय तथा तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि। इन पदों पर भी बदलाव संभावित है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि राज्यपालों की फेरबदल की घोषणा महाराष्ट्र एवं झारखंड के चुनाव-परिणामों की घोषणा के बाद की जायेगी।

रेल आरक्षण...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रद्द करने की अनुमति होगी। ताज एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस आदि जैसी कुछ दिन के समय चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों के मामले में कोई बदलाव नहीं होगा, जहां वर्तमान में अग्रिम आरक्षण के लिए कम समय सीमा लागू है। विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की सीमा के मामले में भी कोई बदलाव नहीं होगा।

सूत्रों के अनुसार, ए.आर.पी. को 60 दिन करने का फैसला इसलिए लिया गया है, ताकि अनुरक्षण कार्य के लिए प्लानिंग में आसानी हो। 120 दिन के ए.आर.पी. में यात्री कम और दलाल ज्यादा बुकिंग करते हैं। इस दौरान अक्सर देखा गया है कि यात्री यात्रा नहीं करते हैं और टिकट रद्द करना भूल जाते हैं। इससे जरूरतमंद यात्रियों को सीटें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। सूत्रों ने कहा कि पहले ए.आर.पी. 60 दिन का ही था। इसको 120 दिन करने का फैसला 31 मई 2020 को किया गया था।

भारत के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लगातार इनकार करता रहा है। भारत का कहना है कि उसका नाम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने के लिए कैनडा ने यह आरोप लगाया था। भारत के पूर्व राजदूत अजय बिसारिया ने कहा कि ट्रूडो के बदले रुख से भारत को दोनो देशों के बीच रचनात्मक संवाद बढ़ाने का अवसर मिला है। ट्रूडो के पीछे हटने से अमेरिकन प्रभाव के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। इससे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंधों की जटिलता भी पता लगती है। इस प्रकरण का कैनडा और भारत पर असर पड़ेगा। पर इससे ट्रूडो कमज़ोर होंगे या मजबूत यह देखा जाना बाकी है।

लंदन में मुख्यमंत्री का...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

(नैरोबैंड आर.एफ. मेश नेटवर्क विकसित करने में दुनिया की अग्रणी कंपनी), जे.सी.बी. (जो कंस्ट्रक्शन और इंडिस्ट्रियल उपयोग वाले वाहन बनाती है और जिसकी राजस्थान में मैनुफैक्चरिंग यूनिट है) और ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स (ब्रिटेन की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी) के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात शामिल है।

इसके अलावा, प्रतिनिधिमंडल ने वॉण्डरलस्ट (जो इंग्लैंड की एक प्रमुख ट्रैवल पत्रिका और वेबसाइट है) के अधिकारियों के साथ भी मुलाकात की और उनसे राजस्थान को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा, एक निवेशक रोड शो में हाल ही में स्वीकृत राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (आर.आई.पी.एस.) 2024 नीति को भी लॉन्च किया जाएगा।

प्रतिनिधिमंडल आज शाम (लंदन समयानुसार) प्रवासी राजस्थानियों से मुलाकात कार्यक्रम में हिस्सा लेगा। प्रवासी राजस्थानियों को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए राज्य सरकार एक विशेष अभियान चला रही है। इसके तहत, अनिवासी राजस्थानी समुदाय से जुड़ने और मातृभूमि के साथ उनके संबंधों को जीवंत बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसके अलावा, अनिवासी राजस्थानी समुदाय से राज्य में निवेश और नए व्यावसायिक उपक्रमों की स्थापना में सहायता करने का भी अनुरोध किया जाएगा।

मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के अलावा इंग्लैंड दौरे पर गए प्रतिनिधिमंडल में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ए.सी.एस.) शिखर अग्रवाल, उद्योग विभाग और ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स (बी.आई.पी.) के आयुक्त रोहित गुप्ता और राजस्थान सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

बिहार में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जानकारी लेकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डी.जी.पी. ने मीडिया को बताया कि घटना के बाद दो स्पैशल इन्वैस्टिगेटिंग टीम गठित की गई हैं। एक सैटअप स्थानीय स्तर पर अपराधिक तत्वों के लिप्त होने का पता लगाएगा तथा दूसरी एस.आई.ई.टी. इस घटना व इससे पहले हुई घटनाओं की जांच करेगी। उसके आधार पर एक्शन प्लान बनाया जाएगा। एक लिकर माफिया का नाम सामने आ रहा है, जो पहले भी ऐसे कांड में लिप्त रहा है। राज्य के शराबबंदी मंत्री रत्नेश साडा ने कहा था कि क्राइम कंट्रोल एक्ट लगाकर शराब माफिया को खत्म कर देंगे।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908